बार तथा भारत में किसी भी स्थान के लिए चार वर्ष के एक ब्लाक में एक बार एल०टी०सी० सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं । भारत में किसी भी स्थान की यात्रा की सुविधा चार वर्ष के ब्लाक के दौरान उपलब्ध दो गृह नगर रियायतों में से एक की एवज में है ।

(ख) चूंकि छुट्टी यात्रा रियायत के दावों की जांच तथा उन पर कार्रवाई विभिन्न मंत्रालयों, विभागों/कार्यालयों से संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है, अतः अलग-अलग मामलों में अनियमितताओं के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) छुट्टी यात्रा रियायत एक ऐसी सुविधा है जो सरकारी कर्मचारी को अपने सामाजिक दायित्व निभाने के लिए दो वर्ष में एक बार गृह नगर जाने अथवा अपने देश की विविध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होने के लिए चार वर्ष में एक बार भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए प्रदान की जाती है । इस सुविधा के एवज़ में नकद भुगतान करना योजना के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा ।

Public grievances

1637. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

i,a) how many public grievances have been registered with the Department during 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(b) in how many cases action has bean initiated to redress the grievances during 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(c) what is the maximum. time taken to dispose of the grievances;

(d) what is the procedure followed after receipt of the grievances; and

(e) whether proper publicity is being given through media about the existence of public grievances department?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) During 1991-92, 1992-93 and 1993-94, 14248, 16711 and 14767 public grievances respectively were receied by the Ministry of Personnel, Public Grievances, and, pensions.

(b) Action has been initiated in all these cases.

(c) The time taken for disposal of a grievances depends upon various factors such as number of agencies/departments involved, nature of grievance, availability of documents and requisite information from the complainant's side, etc. However, all steps are taken to ensure the expeditious disposal of all grievances.

(d) The grievances received by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances are scrutinised and sent to the concerned Ministries/Departments for redressal. Thess grievances are duly acknowledged and the complainant is informs about the interim action taken. The sanction of payment of pension operates on a decentralised basis. Therefore, complaints relating to pension received in the Department of pension and pensioners' Welfare are forwarded to the concerned Ministries/Departments for prompt action. These are, however, monitored by the Department to check delays in their final settlement. The Department also has a standing Committe-; of Voluntary Agencies; (SCOVA) in which twelve prominent Pensioners' Associations are represented. The Minister of State (PP) holds meetings with them twice a year.

(e) Instructions have been issued by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances advising all Ministries/Departments for displaying the name, designation, room number, telephone number etc. of their Director of Grievances at the reception and other convenient peaces, placing a locked complaint box at the reception and strictly oberving meetingless day, on every Wednesday. A Joint Secretary level officer has been designated in every Ministry

as Director of Grievances. Instructions have also been issued to all the Ministries/Departments of the Government of India for issuing booklets/pamphlets about the facilities available to the public. These instructions emphasise that through such publications it may be ensured that the members of the public can approach *the* right authority and follow the prescribed procedure for obtaining the services/facilities easily. They have also been advised that the grievances columns in newspapers should be regularly examined with a view to picking up cases which relate to them and to take action on them in a time-bound manner. Regular meetings are also held by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances on public grievances matters with the Directors of Public Grievances of State Governments as well as Ministries/Departments of the Government of India to review the grievances redressal machinery set up by them. The Department of Pension and Pensioners' Welfare have recently apprised the public through a programme titled 'Pension Tension' which was telecast on Doordarshan Network. This programme apprised the viewers about the pension rulesprocedures and the functioning of the Department. Another programme on pension was telecast on zee T.V. which related to redressal of pensioners' grievances.

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु-सीमा

1638. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिये कितनी अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित की गई है और यह कित वर्ष निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या सरकार को इस अधिकतम आयु-सीमा को बढ़ाये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, यदि हां, तो उन पर क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती के लिये अधिकतम आयु-सीमा में वृद्धि की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार देश की जनसंख्या-वृद्धि से उत्पन्न स्थिति तथा इस समय सरकारी सेवाओं में भर्ती के कम अवसर उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि करेगी और इस संबंध में अब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) मार्च, 1972 से समूह "ग" (तृतीय श्रेणी) के पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। समूह "घ" चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिये भी आयु सीमा 25 वर्ष है।

(ख) हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सिविल सेवा परीक्षा, 1991 से समूह क/ख (प्रथम/द्वितीय श्रेणी) के पद/सेवा पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है।

(घ) समूह ग/घ पदों पर नियुक्ति के लिये विद्यमान अधिकतम आयु सीमा, कार्य की प्रकृति, शैक्षणिक अर्हताओं तथा अनुभव की अपेक्षाओं को देखते हुये निर्धारित की गई है और इसीलिये इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों सीमित होने के कारण अधिकतम आयु सीमा बढ़ा देने मात्र से ही इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या के लिये रोजगार के अवसर स्वतः ही बढ़ नहीं पायेंगे।

Facilities to states consequent on Pnnchayat elections

1639. SHRI RAMJI LAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what assistance/facilities have been provided by Government of India to the States where penehayat elections have been held;